ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-12* January- 2021
Innovation The Research Concept

सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास

Madhya Pradesh in Seventh and Eighth Five-Year Plans of Economic Development

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

रिंकी गिरी गोस्वामी
शोध छात्रा,
इतिहास विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर म.प्र, भारत

सारांश

प्रस्तुत पेपर में सातवीं एवं आंठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास एवं ऋण सम्बंधित कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सातवीं योजना (1985–86 से 1989–90) योजना के आधार–भूत लक्ष्य वृद्धि आधुनिकीकरण आत्म निर्भरता तथा सामाजिक न्याय रहे है। इस योजना का परिव्यय 7000.00 करोड़ रूपये तथा व्यय 6591.18 करोड़ रूपये था। आठवीं योजना (1992–93 से 1996–97) का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं विकास को प्राप्त करना था। इस योजना का परिव्यय प्रथम चार वर्षों (1992–96) की अवधिक में 10461.27 करोड़ रूपये तथा व्यय 9492.59 करोड़ रूपये अनुमानित है। आठवीं योजना में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता लाकर खाद्यान्न निर्यात के समुचित भण्डार उपलब्ध हो सके एवं ऊर्जा यातायात संचार और सिंचाई अधोसंरचना का सुदृढीकरण सम्मिलित कर मध्यप्रदेश को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसार करना प्रमुख उद्देश्य रहा है।

In the paper presented, an attempt has been made to present a brief description of Madhya Pradesh's economic development and loan related works in the seventh and eighth five-year plans. The basic goals of the Seventh Plan (1985-86 to 1989-90) are growth, modernization, self-reliance and social justice. The outlay of this scheme was Rs 7000.00 crores and the expenditure was 6591.18 crores. The main objective of the Eighth Plan (1992–93 to 1996–97) was to achieve agriculture and development. The outlay of this scheme is estimated to be Rs 10461.27 crore and expenditure Rs 9492.59 crore during the first four years (1992-96). In the Eighth Plan, by bringing self-sufficiency in food grains, proper storage of food grains can be available and the main objective has been to move Madhya Pradesh on the path of economic development by including energy traffic communication and strengthening of irrigation infrastructure.

मुख्य शब्द : आत्म–निर्भरता, आर्थिक–विकास, सामाजिक–न्याय।
Self-Reliance, Economic-Development, Social-Justice.

प्रस्तावना

1956 वर्ष में मध्य प्रदेश के गठन की चर्चाओं के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू नें कहा था ''इतना बड़ा प्रदेश कि महाँ भिण्ड और कहाँ रायगढ़ कैसे प्रशासन चलेगा?''44 वर्ष बीत गए और प्रशासन चला। 1 नवम्बर 2000 के दिन वृहत मध्यप्रदेश दो राज्यों में बट गया। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश क्रमशः 113 और 330 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने में समेटे 16 और 45 जिले लिए कार्यरत है। समुचित विकास के लिए दोनों राज्यों में आदर्श सहयोग की अपेक्षा इनकी जनता को सहज करना और स्वाभाविक है चार दशक से अधिक समय साथ रहते और कार्य करते निकटता बनी किन्तु राजनैतिक दाव पेंच में खाई न पैदा हो जाय इसकी सावधानी आवश्यक है। जो हो गया उसकी शिकायत नही है। अब तो 6 करोड़ लोगों के उन्नत जीवन बनाने का अहम सवाल है। उन्नत जीवन के लिए प्रदेश की आय में वृद्धि होना चाहिए।

वर्ष 1956 में 756 करोड रूपयों के आसपास थी वर्ष 1990–91 में 26546 करोड़ हुई और गत दस वर्षों में बढ़कर पैतालीस हजार करोड रूपये को पार कर गई। साथ–साथ जनसंख्या भी बढ़ती गई 1961 में 3 करोड़ 61 लाख

से अधिक हो गई और आज छत्तीसगढ़ के लगभग दो करोड़ लोग कम हो जाने के बाद राज्य में 6 करोड 40 लाख से अधिक लोग रहते है। इसलिए प्रति वर्ग किलोमीटर धनत्व 149 से बढ़कर 196 हो गया जो 1981 में 118 ही था, अधिक धनत्व कम भूमि व्यक्ति अनुपात का सूचक है अधिक लोग का अर्थ है। प्रतिव्यक्ति आय में कम बढ़त होना कम आय होने के कारण जीवन के उन्नत होने में बाधा आती है। जब इसकी अन्य राज्यों विशेषता पड़ौसी राज्यों से तुलना की जाती है। जब राज्य की स्थिति का पता चलता है कि राज्य आर्थिक धरातल पर कहा खड़ा है।

पड़ौसी राज्य गुजरात महाराष्ट्र आन्ध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान है। (छत्तीसगढ़ तो मध्यप्रदेश का ही कल तक अंग था।) इन आठ राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में मध्यप्रदेश सांतवें स्थान पर है।

औद्योगिक नक्शे पर प्रदेश को लाने के लिए शासन द्वारा नई 1994 में औद्योगिक नीति एवं कार्य योजना जारी की गई, इस नीति के अनुसार आदर्श औद्योगिक नगर लघु विकास केन्द्र, डायमण्ड पार्क, इलेक्ट्रानिक्स तथा कृषि एवं शहरी अनुपयोगी पदार्थों के प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थाना हेतु योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया। साथ ही शत प्रतिशत निर्यातक एवं अनिवासी भारतीयों को प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहन करने की विशेष योजना तैयार की गई।

प्रदेश में वृद्ध एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में 22 वृद्ध एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए, जिनमें 1121.00 करोड़ रूपयों का विनियोजन हुआ तथा 3.8 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। लघु कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की भी महत्वकांक्षी योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1994–95 में 19.5 हजार लघु एवं कुटीर उद्योग इकाईयां स्थापित हुई। इनमें 246.21 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 46.1 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्देश्य

1. किसी भी योजना को क्रमबद्ध तरीके से विकसित व्यवस्था की सुचारू रूप से चलाने के कार्य करने की प्रक्रिया को एक समुचित योजना से समझा जा सकता है।
2. आर्थिक विकास में सभी मूल उद्देश्यों को देखते हुए समस्त मानवीय विकास सामाजिक–आर्थिक विकास की संरचना को स्थापित करने के लिए योजना की महत्वपूर्ण सत्यापित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
3. किसी भी संगठित राज्य व समाज की सर्वांगीण विकास एक समुचित व्यवसायी व विकसित अवस्था को समस्त अधोसंरचना के सूत्रीकरण वह आत्मनिर्भरता को ध्यान में रख कर नितः नये लक्ष्य की वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का प्रमुख उद्देश्य रहा है।
4. वर्तमान में चल रही भावी पंचवर्षीय योजना से सीख ले, कर भविष्य में आयोजित होने वाली योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से हो, प्रस्तुत पेपर का उद्देश्य रहा है।

विषय–वस्तु

सातवीं योजना :– योजना के आधारभूत लक्ष्य वृद्धि आधुनिकीकरण आत्म–निर्भरता तथा सामजिक न्याय रहे है सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–86 से 1989–90) में इन लक्ष्यों के साथ ही तीन और आवश्यक उद्देश्य यथा खाधान्न उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि रोजगार के अवसर निर्मित करना तथा उत्पादकता बढ़ाना सम्मिलित किये गये है। साथ ही मानव संसाधनों का तेजी विकास क्षमता उपयोग पर अधिक बल घरेलू प्रौधोगिकीय क्षमताओं का विकास तथा उत्पादन लागत विशेष रूप से औधोगीक क्षेत्र में कम करना उल्लेखनीय है। रोजगार के अवसर बढ़ा कर गरीबी दूर करने के लिये वर्तमान में चल रहे क्रार्यक्रमों के अतिरिक्त विशिष्ट रोजगार कार्य–क्रम जैसे जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ किये गये। इस योजना का परिव्यय 7000,00 करोड़ रूपये तथा व्यय 6591,18 करोड़ रूपये था।1

वार्षिक योजनाएं

केन्द्र में तेजी से बदलते हुए राजनैतिक परिदृश्य के कारण आठवी पंचवार्षिय योजना समय से प्रारम्भ नही हो सकी। इसके स्थान पर दो वार्षिक योजनाएँ (1990–91 तथा 1991–92) चलाई गयी। इन वार्षिक योजनाओं का सविन्यास आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) की अवधारणा पर आधारित है। इनका मूल उद्देश्य रोजगार के अधिक से अधिक अवसरो का सृजन तथा समाजर्थिक परिवर्तन करना था। इन दो वार्षिक योजनाओं का परिव्यय 4426,00 करोड़ रूपये तथा व्यय 3528.38 करोड़ रूपये था।2

आठवी योजना

(1992–93 से 1996–97) का मुख्य उद्देश्य समुचित रोजगार अवसरों का सृजन करना जिससे लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सके, जनसख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करना प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण तथा 15–35 वर्ष के आयु समूह में अशिला को पूर्ण रूप से समाप्त करना, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था एवं प्राथमिकता स्थास्थ सुविधाए बढ़ाना कृषि का विकास एवं विस्तार जिससे खाधान्नों में आत्म निर्भरता लाकर खाधान्न निर्यात के लिए समुचित भण्डार उपलब्ध हो सके एवं ऊर्जा यातायात संचार और सिंचाई अधोसंरचना का सुदृदीकरण सम्मिलित है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आठवी पंचवर्षीय योजना का आकार वर्ष 1991– 92 के भावों पर 11100,00 करोड़ रूपये रखा गया है। कुल योजना प्रावधान का 32,25 प्रतिशत ऊर्जा पर 23,93 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 18.72 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर 7.07 प्रतिशत कृषि एवं सबद्ध सेवाओं पर 4,74 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर 4.20 प्रतिशत उधोग एवं खनिज पर 4.17 प्रतिशत सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 3. 87 प्रतिशत परिवहन पर तथा शेष 1.05 प्रतिशत अन्य क्षेत्रो में है।3

पंचवर्षीय योजना काल में मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास

गत चालीस वर्ष (1951–90) में म.प्र की सात पंचवर्षीय योजना के रूप में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से लगभग 14.020 करोड़

रूपये व्यय किये गये। इस अवधि मे प्रति व्यक्ति लगभग 2,337 रूपये अर्थात् 58 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष योजना व्यय के रूप मे होने का अनुमान है। इन चार दशको मे कृषि ग्रामीण विकास सहकारिका आदि पर 8.956 करोड़ रूपये अर्थात् 63 प्रतिशत उधोग एवं खनिज पर 349 करोड़ रूपये अर्थात् दो प्रतिशत परिवहन एवं संचार पर 691 करोड़ रूपये अर्थात् पाँच प्रतिशत सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओ पर 2.022 करोड़ रूपये अर्थात् कुल योजना व्यय का 16 प्रतिशत होने का अनुमान है दूसरे शब्दो मे मध्यप्रदेश मे पिछले चालीस वर्षो के दौरान योजना व्यय के रूप मे मोटे दौर पर प्राकृतिक साधनो के विकास पर 65 प्रतिशत मानव संसाधन के विकास पर 16 प्रतिशत आर्थिक अथवा भौतिक संसाधनों के विकास पर 16 प्रतिशत एवं अंघोसंरचना के विकास पर लगभग 03 प्रतिशत व्यय किया गया।[4]

योजना व्यय की उस प्रकृति में इन चार दशको मे काफी अन्तर हुआ है। कृषि ग्रामीण विकास सहकारिता आदि क्षेत्रो मे जहाँ प्रथम योजना काल में 34 प्रतिशत व्यय हुआ था वही क्रमशः घटते हुए सातवीं योजना काल के अन्त में सिर्फ 11 प्रतिशत तथा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य पेयजल, आदिवासी व हरिजन कल्याण आदि सामाजिक तथा सामुदायिक सेवओं अर्थात मानव संसाधन विकास पर व्यय प्रथम योजना के 27 प्रतिशत से घटकर सातवीं योजना के अंत में सिर्फ 16 प्रतिशत रह गया। उद्योग परिवहन और संचार सेवाओं में सामान्यतः 05 प्रतिशत व्यय हुआ तथा सभी योजना अवधियों में लगभग यह स्थिरता रही। योजना व्यय में वृद्धि सिर्फ सिंचाई एवं विद्युत पर हुई इन पर प्रथय योजना के 21 प्रतिशत से सातवी योजना के अन्त में यह व्यय बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया।[5]

म.प्र. में इन वर्षों में अर्थात 1961–62 से 1989–90 में लगभग 72 प्रतिशत योजना व्यय अपने स्वतः के साधनों से एवं लगभग 28 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय योजना सहायता से प्राप्त हुआ है इनमें चालू राजस्व से शेष अर्थात चालू तथा वचनवद्ध योजनात्तर व्यय तथा अतिरिक्त संसाधन से लगभग 4955 करोड़ रूपये अर्थात 51 प्रतिशत प्राप्त हुआ। म.प्र. की सन् 1970–71 और 1988–89 की अवधि में प्रदेश की कुल राजकीय आय प्रतिव्यक्ति आय और विभिन्न क्षेत्रों में हुई आय का विवरण हमें उत्साहवर्धक प्रतीत नही होता है। हमारी प्राथमिकताओं विनियोजन एवं कियान्वयन में कहीं न कही कुछ त्रुटि आवश्यक है। इस अवधि में योजनाबद्ध विकास भी हमारी मूलभूत समस्याओं का निराकरण नही हुआ और इसलिए आज भी म.प्र. में गरीबी स्तर 36.2 प्रतिशत है। यह देश के 15 बड़े राज्यों में निम्न स्तर पर ही रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी मंजिले कुछ और थी और राहें कुछ और।[6]

नई सरकार ने कृषि और उद्योगों के विस्तार सिंचाई व विद्युत उत्पादन के विकास जल संसाधनों के विकास सार्वजनिक उपक्रमों को लाभ प्रद बनाने का समय वृहद कार्यक्रम पंचायत राज्य की स्थापना वनों के संरक्षण व्यापार व्यवस्था को नई गति आदि के रूप में अनेक व्यापक प्रभाव वाले प्रयास प्रारंभ किये हैं।[7]

वर्ष 1980–90 में वृहद एवं मध्यम लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास हतु 52.27 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था, वर्ष 1990–91 के दौरान वृहद एवं मध्यम लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु राज्य आयोजना मद से 51.62 करोड़ रूपये का प्रावधान है। वर्ष 1988–89 में 33 वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हुई। जबकि वर्ष 1989–90 में इसी श्रेणी के 42 नए उद्योगो की स्थापना से इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। वर्ष 1989–90 के अन्त तक कुल 521 बडे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित हो चुके हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष वार प्रगति निम्नानुसार है।[8]

वर्ष	स्थापित ईकाइयों की संख्या	पूजी निवेश (करोड़ रूपये में)	रोजगार (संख्या)
1985–86	46	193.91	6340
1986–87	52	406.52	6492
1987–88	31	679.59	3998
1988–89	33	68.00	3000
1989–90	42	170.00	3898

संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप आंठवी पंचवर्षीय (1990–95) में योजना आयोग के दृष्टिकोण के आधार पर योजना पर कुल परिव्यय का कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को यथा सम्भव रोजगार की व्यवस्था योजनाओं एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण और देश के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की यथासम्भव कम करना है। आठवीं योजना लगभग 6 लाख करोड़ रूपयों की होगी। जिसमें म.प्र. का अंशदान लगभग 13 हजार करोड़ रूपयों का होगा। योजना कार्यक्रमों में सामान्यतः 85.71 प्रतिशत वृद्धि होगी तथा कुल प्रावधान में से 4.4225 करोड़ रूपये जिला योजनाओं पर आदिवासी उपयोजनाओं पर 2.987 करोड़ रूपये तथा अनुसूचित जातियों में विशेष उत्थान के प्रयासों पर लगभग 1.365 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगें। इस तरह राष्ट्रीय के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास होगा। जहाँ सन् 1951–90 के मध्य लगभग 14 हजार करोड़ रूपये व्यय किये गये, वही सिर्फ आठवीं योजना में लगभग 13 हजार करोड़ रूपये व्यय होगें। दूसरे शब्दों में जहां पिछली सातों योजनाओं (1951–90) के मध्य प्रति व्यक्ति लगभग 2.337 रूपये अथवा औसतन 58 रूपये प्रति वर्ष खर्च किये गये। वहीं आठवीं योजना में लगभग 2.167 रूपये अथवा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 433 रूपये खर्च होने का अनुमान है। आठवीं योजना में कृषि ग्रामीण विकास एवं सहकारिता पर लगभग 1.493 करोड़ रूपये व्यय होगें जबकि सातवीं में सिर्फ 737 करोड़ रूपये व्यय किये गये थे। इसी प्रकार सातवीं योजना के 4.637 करोड़

रूपये की अपेक्षा आठवी योजना में लगभग 7.303 करोड़ रूपये सिंचाई एवं विद्युत पर व्यय किये जायेंगें।9

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1990–91 के दौरान नवम्बर 1990 तक मध्यप्रदेश में 16 वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई। जिनमें 54.65 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा लगभग 1683 व्यक्तियों को रोजगार मिला। साथी ही नवीन वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 1990–91 में जुलाई 1990 तक भारत शासन द्वारा प्रवेश हेतु 93 आशय–पंजीयन पत्र भी जारी किये गये। भारत शासन द्वारा प्रदेश के 18 जिलों (शिवपुरी, छत्तरपुर, सरगुजा, सिवनी, नरसिंहपुर, धार, झाबुआ, भिन्ड, मण्डला, पन्ना, राजगढ़, गुना, सीधी, बालाघाट, दमोह, दतिया, छिन्दवाड़ा तथा टीकमगढ़) को उद्योग विहीन घोषित किये जाने से आपेक्षित नीति के अनुसार इनमें से 16 जिलों में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हुई है।[10]

प्रदेश में वृहद एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन उद्योगपतियों को तत्संबंधी जानकारी देने उद्योग स्थापना में आने वाली कटिनाईयों के निराकरण और मार्गदर्शन हेतु निगम में पृथक से औद्योगिक सहायता केन्द्र (औद्योगिक प्रोत्साहन) कार्यरत है। वर्ष 1990–91 के दौरान जुलाई 90 तक प्रदेश में वृहद एवं मध्यम श्रेणी की 10 नवीन औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित हुई हैं। प्रदेश में प्राकृतिक गैस के आधार पर विजयपुर (गुना में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उर्वरक कारखाने के अतिरिक्त एक गैस क्रेकिंग प्लांट की स्थापना हेतु आशय पत्र प्रदाय के लिए आवेदन देने के साथ ही तेल शोधक कारखाने एवं पेट्रोकेमीकल्स उद्योगों की स्थापना हेतु निगम प्रयासरत है तेल शोधक कारखाने की स्थापना से प्रदेश में अन्य अनेक प्रकार के सहायक उद्योग सीापित होने की अच्छी सम्भावनऐं है।11

राज्य शासन की ओर से प्रदेश में औद्योगीकरण की दिशा में गति लाने के लिए पृथम से कई उपक्रम छठे दशक के प्रारम्भ में स्थापित किये गये। उदाहरण के तौर पर म.प्र. राज्य उद्योग निगम म.प्र. औद्योगिक विकास निगम म.प्र. लघु उद्योग निगम, म.प्र. वित्त निगम आदि। सातवें दशक में राज्य में उद्योग के विस्तार में और आर्थिक गति जिला उद्योग केन्दों के माध्यम से हुई। ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक की दिशा में एक क्रान्ति के रूप में आठवां दशक माना जा सकता है। जब राज्य शासन द्वारा उद्योगों के लिये आवश्यक अधोसंरचना के विकास के लिए औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की स्थापना की गई।12

मध्यप्रदेश में वर्ष 1990–90 को औद्योगीकरण की दृष्टि से यदि नई क्रान्ति अथवा लहर का वर्ष कहा जाए तो अतियोक्ति नही होगी। राज्य शासन के प्रयासों से पिछले डेढ़ वर्षों में प्रदेश में जिस तेजी से नये–नये उद्योग लगाये गये है। तथा अनेक नये उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वह उल्लेखनीय है चाहे सीमेन्ट तथा सोयाबीन उद्योग हों अथवा इलेक्ट्रानिक्स या बड़े–बड़ इस्पात संयंत्रों की बात हो मध्यप्रदेश ने देश के औद्योगिक मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाया है, आज स्थिति यह है कि प्रदेश के करीब 20 हजार करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के लिये मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 1990–91 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश इलेक्ट्रनिक्स विकास द्वारा 45 करोड़ रूपये लागत की उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित आप्टो इलेक्ट्रानिक्स–कम्युनिकेशन सिस्टम परियोजना (आप्टिकल फाईबर) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर इस क्षेत्र में नया आत्मविश्वास जगाया गया है। यह महत्वकांक्षी परियोजना प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के विकास के मार्ग में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इस कड़ी में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को उच्चस्तरीय टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 3.26 करोड़ रूपये से इन्दौर से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी।[13]

वर्तमान आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान म.प्र. में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्य प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 80 प्रतिशत निवासियों के कल्याण के लिये विभिन्न विकास योजनाओं पर इस वर्ष 524.27 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है। यह राशि पिछले वर्ष की राशि से डेढ़ गुना है। देश में ग्रामीण विकास कार्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तथा आर्थिक संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के साथ–साथ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।[14]

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों (आई.आर.एस. –1–ए) तथा (आई.आर.एस.–1–वी) ने भारत में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में क्रान्ति ला दी है। वर्ष 1988 और 1991 में अपेक्षित इन उपग्रहो से प्राप्त चित्रों से कृषि उत्पादन तथा कृषि क्षेत्र का सही–2 आंकलन सूखग्रस्त हो जाने वाले क्षेत्रों में निगरानी और आकलन भूमि उपयोग के मानचित्रीकरण पडती भूमि के प्रबंधिन जल संसाधन के प्रबंधन नगरी विकास खनिजों की खोज बन संसाधनों के सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आये है अकूत प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर होने के बाद भी इस प्रदेश की गरीबी और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण इस संपदा का वैज्ञानिक पद्धति से दोहन न हो पाना है। अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अन्तर्गत 1984 में स्थापित राज्य स्तरीय सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में प्रदेश की प्राकृतिक संपदा के दोहन की दिशा में उत्साहजनक कार्य किये है। इस दिशा में म.प्र. सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र ने महत्वपूर्ण शुरूआत की है, केन्द्र ने प्रदेश के 3 हजार गांवों के आसपास सुदूर संवेदन तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे स्थानों का पता लगाया जहां पानी मिल सकता है। इसके उत्साहजनक परिणाम निकले और इन क्षेत्रों में नलकूपों की सफलता बढ़ कर 85–90 प्रतिशत तक पहुंच गई।

भोपाल मंडीदीप , विदिशा, बुरहानपुर, जबलपुर, उज्जैन, इन्दौर, नागदा तथा नेपानगर में यह कार्य 1.50. 000 तथा 1.20.000 मापक पर किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंदा पानी तथा कारखानों से निकले अनुपयोगी विषाक्त पदार्थों को नदियों में पहुंचने से रोकना है।

आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंदसौर, दतिया, रायपुर, रायसेन, बैतूल, शहडोल, धार, खरगौन तथा देवास जिलों में उक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित

है। इस प्रकार म.प्र. में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की अच्छी शुरूआत हो गई।[15]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते है कि मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास आजादी के बाद से ही भारत में योजनात्मक विकास की ओर ध्यान दिया गया। पंचवर्षीय योजनाऐं इसका उदाहरण है कि बिना योजना के एक भी कदम सही दिशा में आगे नही बढ़ सकता है, और न ही वांछित लक्ष्य प्राप्त होता है क्रियान्वयन के लिए योजना आवश्यक ही है। मध्यप्रदेश में भी राज्य गठन के बाद पंचवर्षीय और अन्य विकासात्मक योजनाओं का निर्माण कर उन्हे लागू किया गया। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के परिणाम आज हमारे सामने हैं, वर्तमान में प्रदेश में योजनात्मक विकास के प्रति नई सोच पैदा हुई है। अब योजना निर्माण और क्रियान्वयन इन दोनों ही ध्रवों को समान महत्व दिया जा रहा है। राज्य की वर्ष 94–95 की वार्षिक योजना के आकार में पूर्व के वर्ष की तुलना में साढे चौदह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और उसके लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास इसका उदाहरण है।

इस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य को औद्योगिक दृष्टि सम्पन्न बनाने की दिशा तेजी से कदम बढ़ाये है। इस उद्देश्य में काफी हद तक सफलता भी मिली है। अब वह दिन दूर नही जब मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान कायम करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *फाइल म.प्र. विशेषांक, मध्यप्रदेश में प्रगति के चालीस वर्ष आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, पृष्ठ–76*
2. *वही – पृष्ठ – 77*
3. *वही – पृष्ठ – 78*
4. *मध्यप्रदेश सन्देश – 1991 वर्ष – 87 अंक, 1 जनवरी 1991, सम्पादक अरविन्द्र चतुर्वेदी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. जहांगीराबाद भोपाल, पृष्ठ – 32*
5. *वही, पृष्ठ – 33*
6. *वही, पृष्ठ – 34*
7. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 87, अंक–5, 10 मार्च 1991, सम्पादक अरविन्द्र चतुर्वेदी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. जहांगीराबाद भोपाल, पृष्ठ – 12*
8. *मध्यप्रदेश वार्षिकी विकास स्वदेश भोपाल का प्रकाशन – 1992–93, प्रकाशक– श्रीमति अरूणा शर्मा, संचालक–श्री राधिका प्रकाशन प्रा.लिमिटेड, भोपाल, स्वदेश प्रिंटर्स पंजीयन क्रमांक – आर.एन. 35035/79, पृष्ठ–141*
9. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 87, अंक–5, 10 मार्च 1991, सम्पादक अरविन्द्र चतुर्वेदी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. जहांगीराबाद भोपाल, पृष्ठ – 55*
10. *मध्यप्रदेश वार्षिकी विकास स्वदेश भोपाल का प्रकाशन – 1992–93, प्रकाशक– श्रीमति अरूणा शर्मा, संचालक–श्री राधिका प्रकाशन प्रा.लिमिटेड, भोपाल, स्वदेश प्रिंटर्स पंजीयन क्रमांक – आर.एन. 35035/79, पृष्ठ–142*
11. *मध्यप्रदेश वार्षिकी विकास स्वदेश भोपाल का प्रकाशन – 1992–93, प्रकाशक– श्रीमति अरूणा शर्मा, संचालक–श्री राधिका प्रकाशन प्रा.लिमिटेड, भोपाल, स्वदेश प्रिंटर्स पंजीयन क्रमांक – आर.एन. 35035/79, पृष्ठ–151*
12. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 87, अंक–12, 25 जून 1991, सम्पादक अरविन्द्र चतुर्वेदी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. जहांगीराबाद भोपाल, पृष्ठ – 02*
13. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 87, अंक–21, 10 नवम्बर 1991, सम्पादक अरविन्द्र चतुर्वेदी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. जहांगीराबाद भोपाल, पृष्ठ – 17*
14. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 88, अंक–8, अगस्त 1993, सम्पादक एन. के तिवारी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. टैगोर मार्ग, वाणगंगा, भोपाल, पृष्ठ – 23*
15. *मध्यप्रदेश संदेश वर्ष 88, अंक–11, नवम्बर 1993, सम्पादक एन. के तिवारी, सम्पर्क – जनसम्पर्क संचालनालय म.प्र. टैगोर मार्ग, वाणगंगा, भोपाल, पृष्ठ – 30*